



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 492]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 28, 1994/आश्विन 6, 1916

No 492] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 28, 1994/ASVINA 6, 1916

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय
(विधायी विभाग)

अधिमूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 1994

अतः, मैं, शंकर दयाल शर्मा, भारत का राष्ट्रपति श्री
थंगा मरुथामुथु की उपरोक्त अर्जी को स्वीकार करता हूँ।

सितम्बर 19, 1994

भारत का राष्ट्रपति

का. प्रा. 713(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्न-
लिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित
किया जाता है:—

आदेश

तिरुचिरापल्ली के एक अधिवक्ता श्री थंगा मरुथामुथु
द्वारा 3-1-1994 को एक अर्जी फाइल की गई है जिसमें यह
अभिकथन किया गया है कि लोक सभा के एक आसीन सदस्य
श्री एल. अदकलराज ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951
(1951 का 43) की धारा 9क के साथ पठित संविधान के
अनुच्छेद 102 के खंड (i) के अधीन निरर्हता उपगत की है;

और भारत के राष्ट्रपति ने उक्त अर्जी के प्रति निर्देश से
संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (2) के अधीन निर्वाचन
आयोग से राय मांगी है;

और निर्वाचन आयोग की यह राय है (उपाबंध देखिए) कि
श्री एल. अदकलराज ने संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड
(i) के अधीन निरर्हता उपगत नहीं की है;

[फा. सं. 7(43)/94-वि. 2]

टी. के. विणवानाथन, संयुक्त सचिव
एवं विधि सलाहकार

उपबंध

भारत निर्वाचन आयोग

भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष

1994 का निर्देश मामला सं. 1

[भारत के राष्ट्रपति से भारत के संविधान के अनुच्छेद
103(2) के अधीन निर्देश]

राय

भारत के राष्ट्रपति से भारत के संविधान के अनुच्छेद
103(2) के अधीन यह निर्देश भारत निर्वाचन आयोग की
इस प्रश्न पर राय आरम्भ करने के लिए है कि क्या लोकसभा

के आसीन सदस्य श्री एल. अदकलराज, जो नमिलनाडु राज्य में 27-तिरुचिरापल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जून, 1991 में निर्वाचित हुए हैं, संविधान के अनुच्छेद 102(1) के अधीन निरहता से अस्त हो गए हैं।

2. उपरोक्त प्रश्न को तिरुचिरापल्ली के श्री थंगा मरुथामुथु, अधिवक्ता ने तारीख 3-1-1994 की अपनी अर्जी द्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103(1) के निर्बंधनों के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति के समक्ष उठाया है

3. अर्जीदार ने यह अभिकथन किया है कि दक्षिण रेल द्वारा आरंभ किए गए भवनों के निर्माण और अनुरक्षण तथा सिविल संकर्म के निष्पादन के लिए कई संविदाएं करने के कारण प्रत्यर्थी श्री एल. अदकलराज, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (जिसमें इसमें इसके पश्चात् "1951 अधिनियम" कहा गया है) की धारा 9क के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 102 (1) के अधीन निरहता को प्राप्त हो गए हैं। उसने अभिकथन किया है कि यद्यपि ये संविदाएं प्रत्यर्थी के पुत्र के नाम से की गई हैं तथापि वास्तव में ये वे संविदाएं हैं जो प्रत्यर्थी द्वारा अपने व्यापार और कारबार के अनुक्रम में की गई हैं। अर्जीदार ने उक्त आशय के अभिकथनों को उसके अपने शब्दों में कहना उचित होता है जैसा कि उसने राष्ट्रपति को प्रस्तुत अपनी उपर्युक्त अर्जी में कहा है :—

"3. प्रत्यर्थी के पिता स्वर्गीय ए.एस.जी. लोदुसामी दक्षिण रेल, तिरुचिरापल्ली मंडल के साथ भवनों के निर्माण और अनुरक्षण संकर्म की संविदाओं का निष्पादन करते रहे हैं और दक्षिण रेल, तिरुचिरापल्ली द्वारा पट्टे पर दी गई भूमि पर उनकी एक पेट्रोल कोठरी (बैंक) भी थी।

(4) प्रत्यर्थी को दक्षिण रेल तिरुचिरापल्ली मंडल से भवनों के निर्माण, संकर्म और अनुरक्षण संकर्म के लिए संविदाएं प्राप्त हुई थीं जो उसके पिता स्वर्गीय श्री ए. एस.जी. लोदुसामी पिल्लई के नाम पर थी।

(5) (1) प्रत्यर्थी ने अपने पुत्र जोसेफ लुइस के नाम से दक्षिण रेल, तिरुचिरापल्ली मंडल के साथ निम्नलिखित के भनिर्माण के लिए सिविल संकर्म के निष्पादन के लिए संविदाएं की हैं :—

- (क) तिरुचिरापल्ली—पुडुक्कोट्टाई रोड में 1 2 कि.मी. दूर माल गोदाम रोड पर 3.5 करोड़ रु. की लागत से एक ऊपरि-पुल (ब्रॉवहर ब्रिज)।
- (ख) रेल-स्टेशनों के लिए भवन,
- (ग) स्टाफ क्वार्टर्स (कर्मचारियों के लिए मकान),
- (घ) अस्पताल, और
- (ङ) अन्य भाग।

(2) प्रत्यर्थी ने अपने पुत्र जोसेफ लुइस के नाम पर दक्षिण रेल, तिरुचिरापल्ली जिला (मंडल) के साथ तिरुचिरापल्ली मंडल में दक्षिण रेल के भवनों के अनुरक्षण संकर्मों के निष्पादन के लिए संविदाएं की।

(3) प्रत्यर्थी ने, क्योंकि वह समद के आसीन सदस्य हैं, एक रेल कर्मकारी को अर्थात् श्री एम. गोपालन, पुत्र श्री आर. नटराजा मय्यर, 22, नांधी कोइल स्ट्रीट, त्रिचि-2 पर अक्षर झाला और दक्षिण रेल से ऐसे संकर्म के लिए बहुत बड़ी रकम प्राप्त की जिसे उसने निष्पादित नहीं किया था और अपने पुत्र जोसेफ लुइस के नाम पर किए गए कार्यों के लिए बड़ी हुई वरों पर संशय प्राप्त किया।

(4) प्रत्यर्थी ने दक्षिण रेल के साथ संविदा संकर्म के निष्पादन के प्रयोजन के लिए रेल सुरक्षा बल (आर. पी. एफ.) के कार्यालय, तिरुचिरापल्ली-1 के निकट दक्षिण रेल के एक भवन को अधिभोग में ले रखा है। प्रत्यर्थी का टेलीफोन सं. 41155, दक्षिण रेल के साथ संविदा संकर्म के निष्पादन के लिए उपरोक्त रेल भवन में लगाया गया था।

(5) प्रत्यर्थी ने अपने कौटुम्बिक कारबार एल. ए. ग्रुप के माध्यम से ज्येष्ठ इंजीनियरिंग आंकड़ा प्रसंस्करण प्रबंधक—कंप्यूटर सेंटर, दक्षिण रेल को 4-एआर. अपार्टमेंटम तिरुवक्कम्बूर, तिरुचिरापल्ली-13 पर आवासीय स्थान उपलब्ध कराया।

(6) प्रत्यर्थी अपने कौटुम्बिक कारबार में—अर्थात् दक्षिण रेल तिरुचिरापल्ली के साथ उपरोक्त पुत्र और भवनों के संनिर्माण और भवनों के अनुरक्षण के संविदा संकर्मों के निष्पादन में, हितबद्ध है।

(7) प्रत्यर्थी वास्तविक संविदाकारी पक्षकार है। उसका पुत्र जोसेफ लुईस केवल नाम के लिए ही है, उसके पुत्र जोसेफ लुइस के नाम से प्रत्यर्थी के कौटुम्बिक कारबार, एल. ए. ग्रुप और दक्षिण रेल के बीच संविदाएं संयुक्त कुटुंब की ओर से और उसके फायदे के लिए की गई हैं, जिसका प्रत्यर्थी मुखिया है।

(8) प्रत्यर्थी अपने शासकीय संसद सदस्य पत्र पैड का उपयोग करके, जिस पर भारत सरकार का लोगो है, अपने कौटुम्बिक कारबार के फायदे के लिए रेल-गाड़ियों में स्थान-सुविधा के लिए आपात कोटा सुविधाओं का उपयोग किया है और कर रहा है।

(6) विधि की यह अपेक्षा है कि अभ्यर्थी का सरकार के साथ हुई किसी संविदा में कोई हित नहीं होना चाहिए और यदि किसी भागीदार का भी हित है तो वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 9क के उपबंधों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त है।

(7) ऊपर पैरा 3, पैरा 4, पैरा 5 में कथित तथ्यों से और पैरा 6 में कथित विधि के अनुसार प्रत्यर्थी ने, जब उसने भारत सरकार—दक्षिण रेल—तिरुचिरापल्ली मंडल, के साथ अपने पुत्र जोसेफ लुईस के नाम से संविदाएं की थीं, जो अभी भी विद्यमान हैं, तब उसने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,

1951 की धारा 9क का उल्लंघन किया है और इसलिए प्रत्यर्थी भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (ङ) के अधीन संसद के किसी भी सदन का सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए निरहित है।

(8) (i) प्रत्यर्थी कौटुंबिक कारबार के रूप में होटल कारबार कर रहा है और उसके पास 3/14, मैकडानल्डम रोड, तिरुचिरापल्ली - 1 पर जेनोज रेजिडेन्सी (पूर्व नाम राजाली होटल) नामक एक तीन सितारा होटल है जो लगभग 6 करोड़ रुपये का है। प्रत्यर्थी का पुत्र, ए. जोसेफ फ्रांसिस (1991 में आयु 23 वर्ष) इस होटल का प्रबंध निदेशक है, उसका तीसरा पुत्र, ए. जोसेफ विन्सेंट (1991 में आयु 21 वर्ष) उसकी पत्नी श्रीमती रानी अदकलराज और उसकी पुत्रवधु श्रीमती शोला लुइस (1991 में आयु 20 वर्ष) होटल के निदेशक हैं। श्रीमती शोला लुइस, उसके प्रथम पुत्र जोसेफ लुइस की पत्नी है जिसके नाम से दक्षिण रेल के साथ उसकी संविदाएं हैं।

(ii) प्रत्यर्थी उपर्युक्त होटल के माध्यम से सभ्य सरकार के विभागों को और भारत सरकार के उपक्रमों अर्थात् नेल और प्राकृतिक गैस आयोग, कावेरी और मेगोमानम परियोजनाओं को खालपान तथा स्थान प्रसुविधाएं प्रदान कर रहा है।

(9) ऊपर पैरा 8 में कथित तथ्यों से, प्रत्यर्थी ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 9क के उपबंधों का अतिक्रमण किया है और इसलिए वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (ङ) के अधीन संसद के किसी भी सदन का सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए निरहित है।

(10) (ख) प्रत्यर्थी ने भवन के मूल्यांकन के लिए विहित मानकों को अपनाए बिना जैनी प्लाजा नामक अपने कौटुंबिक कारबार के भवन के एक तल का, उपर्युक्त भवन के विक्रय के लिए संविदा करने के पश्चात् प्रति उच्च दर पर इंडियन बैंक को विक्रय किया था जिसमें इस समय इंडियन बैंक तिरुचिरापल्ली का प्राञ्चलिक कार्यालय कार्य कर रहा है।

(11) ऊपर पैरा 10 में कथित तथ्यों से प्रत्यर्थी और उसके पुत्र एक संयुक्त कौटुंबिक कारबार कर रहे थे जिनमें प्रत्यर्थी उसका अध्यक्ष और कुटुंब का कर्ता है। वे संयुक्त कुटुंब के फायदे के लिए कारबार कर रहे थे। अपनी कम्पनियों के लिए ऋण सुविधा या उपभोग करने और अपने भवन के एक तल का विक्रय करने में राष्ट्रीयकृत बैंक (इंडियन बैंक के साथ अपने कौटुंबिक कारबार द्वारा की गई सभी संविदाओं में प्रत्यर्थी का हित है और इसलिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 9क के उपबंध लागू होते हैं, अतः प्रत्यर्थी भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (ङ) के अधीन संसद के किसी भी सदन का सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए निरहित है।

(16) (i) "ताड़ी सम्राट" और संसद सदस्य, प्रत्यर्थी ने पेप्सी परियोजना को अनुमति देने के लिए स्व. राजीव गांधी पर दबाव डालने के लिए हर तरह की युक्तियां का आश्रय लिया था। प्रत्यर्थी को दक्षिण के लिए पेप्सी को,

बोतरास और पञ्चक सेक्टर पंजाब कृषि उद्योग निगम जो परियोजना के तीन भागीदार थे, के द्वारा अत्याधिक लाभकारी विशेषाधिकार प्रदान किए गए थे। उपर्युक्त संविदा स्वीकार करके प्रत्यर्थी ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 9क का अतिक्रमण किया है।

(23) प्रत्यर्थी ने भारत सरकार के इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड से ल्यूक्स गोडाउन की संविदा की है जो मैसर्स ए. एस. जी. लोर्दुसामी पिल्लई एंड सन्स के नाम में 114/1-बी, बाईपास रोड, तिरुचि - 10 पर चल रहा है, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 9क को आर्काषित करता है और उससे वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (ङ) के अधीन संसद के किसी भी सदन का सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए निरहित है।

(24) प्रत्यर्थी के एल.ए. ग्रुप ने नेशनल इन्शोरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ एक संविदा की है और उन्हें अपने ए. आर. भवन, तिरुवेकम्बूर, त्रिचि - 13 में कार्यालय स्थान सुविधा प्रदान की है। प्रत्यर्थी ने इस कृत्य द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 9क का अतिक्रमण किया है और इसलिए वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (ङ) के अधीन संसद के किसी भी सदन का सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए निरहित है।

4. अर्जीदार ने यह भी अभिकथन किया है कि प्रत्यर्थी ने अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अनुपाती विपुल धनराशि एकत्रित करके, गहरी भूमि परिसीमा अधिनियम के अतिक्रमण में विशाल संपत्तियां क्रय करके, अपनी पदीय स्थिति का दुरुपयोग कर अपने कौटुंबिक कारबार के लिए बैंकों से बड़ी मात्रा में ऋण लेकर, टेलीफोन बिलों का भुगतान न करके, तिरुचिरापल्ली जनपद कल्याण निधि समिति से पट्टे पर लिए गए एक सिनेमा थियेटर के किराए का संदाय न करके और यह मिथ्या पोषणा करके कि उसने मिश्रित इंजीनियरी में डिप्लोमा पूरा कर लिया था, संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (ङ) के अधीन निरर्हता उपगत कर ली है।

5. अर्जीदार ने यह भी अभिकथन किया है कि प्रत्यर्थी, विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा रखने अथवा अनुपक्षित के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 102(1)(घ) के अधीन निरहित है क्योंकि वह अपने एक पुत्र के माध्यम से, जो संयुक्त राज्य अमरीका में रहता है, अंतरराष्ट्रीय धन दोहन संक्रियाओं में लिप्त है और उसके कुटुंब के पास एक जापानी मेक को टोयोटा कोरीना कार है।

6. प्रत्यर्थी ने, 7-3-1994 के अपने लिखित कथन में, अर्जीदार के सभी आरोपों से इंकार किया है। उसने यह कथन किया है कि अर्जीदार द्वारा जिन सभी संविदाओं का उल्लेख किया गया है वे उसके पुत्र द्वारा की गई हैं जो वयस्क है और अपना स्वतंत्र कारबार कर रहा है और यह कि उसे 1984 के बाद जब वह पहली बार लोक सभा के लिए निर्वाचित हुआ था, उन संविदाओं के साथ कुछ भी लेना-देना नहीं है। उसने यह भी संकेत किया है कि इसी अर्जीदार ने

मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष 1990 की अर्जी सं. 1 में इन्हीं संविदाओं के प्रश्न उठाए थे यह अर्जी उसने 1989 में हुए लोक सभा के निर्वाचन में प्रत्यर्थी के निर्वाचन को चुनौती देते हुए फाइल की थी और यह कि मद्रास उच्च न्यायालय ने अपने 2-7-1992 के आदेश द्वारा अर्जीदार के अभिकथनों को अस्वीकार करते हुए निर्वाचन अर्जी खारिज कर दी थी। उसने यह कहा है कि मद्रास उच्च न्यायालय का अभिनिश्चय पूर्व—न्याय है। और अर्जीदार को संविधान के अनुच्छेद 103 के अधीन उसी मामले को राष्ट्रपति और निर्वाचन आयोग के समक्ष न्यायनिर्णयन किए जाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जा सकता है।

7. प्रत्यर्थी ने अपने पूर्वोक्त लिखित कथन में आय के ज्ञात स्रोतों के अनुपात में धन को इकट्ठा करने, बैंकों से ऋण लेने, स्थावर संपत्ति ऋण करने, टेलीफोन के बिलों का संदाय न करने, पट्टा संपत्ति के संबंध में किराए का संदाय न करने, आदि से संबंधित सभी अभिकथनों से भी विनिर्दिष्ट रूप से इंकार किया है। प्रत्यर्थी ने इस बात से भी इंकार किया है कि वह किसी विदेशी राज्य के प्रति किसी निष्ठा या अनुषक्ति की अभिव्यक्ति के अधीन है।

8. अर्जीदार और प्रत्यर्थी दोनों को 18-8-1994 को आयोग द्वारा सुना गया था। जबकि अर्जीदार स्वयं उपस्थित हुआ था, प्रत्यर्थी का प्रतिनिधित्व उसके विद्वान ज्येष्ठ काउंसल श्री सी. एस. वेंकनाथ द्वारा किया गया था।

9. मेरे द्वारा अर्जीदार के अभिकथनों और उसके समर्थन में उसके द्वारा किए गए मौखिक निवेदनों और उन अभिकथनों के खंडन में प्रत्यर्थी की और से ज्येष्ठ काउंसल के मौखिक निवेदनों पर कार्यवाही किए जाने से पहले अधिकारिता और जांच की परिधि, जो संविधान के अनुच्छेद 103 के अनुसार राष्ट्रपति और निर्वाचन आयोग कर सकते हैं, के संबंध में सांविधानिक और विधिक स्थिति को बताया जाना उचित होगा। निर्वाचन आयोग बनाम साका बैकट राव (ए.आई.आर. 1953 एस. सी. 210), वृन्दावन नायक बनाम भारत निर्वाचन आयोग (ए.आई.आर. 1965 एस.सी. 1892), निर्वाचन आयोग बनाम एन.जी. रंगा (ए.आई.आर. 1978 एस.सी. 1609), आदि में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों की श्रृंखला द्वारा अब यह सुस्थापित हो गया है कि संविधान के अनुच्छेद 103 के अधीन संसद के किसी पदासीन सदस्य की निरर्हता के संबंध में केवल वे ही प्रश्न राष्ट्रपति के समक्ष उठाए जा सकते हैं और निर्वाचन आयोग द्वारा जांच किए जा सकते हैं, जिसका वह सदस्य, उक्त सदस्य के रूप में अपने निर्वाचन के पश्चात् विषय बना है। दूसरे शब्दों में आयोग अनुच्छेद 103 के अधीन केवल किसी सदस्य के निर्वाचन पश्चात् निरर्हता के मामले में जांच कर सकता है। ऐसी किसी निरर्हता से संबंधित किसी प्रश्न को, जिससे उक्त सदस्य अपने निर्वाचन से पूर्व में या निर्वाचन के समय ग्रस्त था, अर्थात् निर्वाचन पूर्व निरर्हता को केवल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के भाग 6 के साथ पठित संविधान के

अनुच्छेद 329(ख) के उपबंधों के अनुसार संबंधित उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई एक निर्वाचन अर्जी के माध्यम से ही उठाया जा सकता है।

10. अतः निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 103 के अधीन वर्तमान कार्यवाहियों में केवल उन्हीं संविदाओं की जांच कर सकता है जो प्रत्यर्थी ने जून, 1991 में लोक सभा के लिए अपने निर्वाचन के पश्चात् की है।

इसके अतिरिक्त, यह प्रत्येक प्रकार की संविदा के मामले में नहीं है, जो 1951 के अधिनियम की धारा 9 क के निरर्हता खंड को आकर्षित करती है। उक्त धारा के अधीन, समुचित सरकार के साथ केवल दो प्रकार की संविदाएं निरर्हता से संबंधित उपबंधों को आकर्षित करती हैं, अर्थात् (i) समुचित सरकार को माल के प्रदाय के लिए संविदाएं और (ii) सरकार द्वारा लिए गए किसी संकर्म के निष्पादन के लिए संविदाएं 1951 के अधिनियम की धारा 7(क) में परिभाषा के आधार पर "समुचित सरकार" से इस मामले में केन्द्रीय सरकार से अभिप्रेत है।

11. अर्जीदार में अपनी अर्जी में इस बात का कहीं भी यह कथन नहीं किया है कि उन संविदाओं में से कौन सी संविदा प्रत्यर्थी के जून 1991 में लोक सभा के लिए निर्वाचन के पश्चात् की गई थी और निष्पादित की गई थी यदि उसके पक्ष में यह धारणा कर भी ली जाए कि प्रत्यर्थी के पुत्र के नाम से की गई संविदाएं प्रत्यर्थी द्वारा ही की गई थी। वस्तुतः संपूर्ण अर्जी में किसी एक संविदा की भी तारीख नहीं बताई गई है।

12. सुनवाई में अर्जीदार से अभिकथित संविदाओं की तारीख बताने के लिए विनिर्दिष्ट रूप से कहा गया था। वह कोई एक तारीख भी या किसी संविदा की कोई अनुमानित तारीख भी उद्धृत करने में असफल रहा। उसने कथन किया कि वह मंडल प्रबन्धक, दक्षिण रेल जैसे संबंधित प्राधिकारियों से, रेल द्वारा 1962 से 1992 तक प्रत्यर्थी के पिता या प्रत्यर्थी या प्रत्यर्थी के पुत्र के साथ की गई सभी संविदाओं को प्रस्तुत करना चाहेगा। इसी प्रकार वह यह चाहते थे कि आयोग द्वारा इंडियन बैंक के अध्यक्ष, तिरुचिरापल्ली, मद्रास, नई दिल्ली में दूर संचार के महा प्रबन्धकों और विभिन्न समाचारपत्रों, जैसे हिन्दू सूर्या इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, दिनामालार, थायी के संपादकों विज्ञापन प्रबन्धकों रिपोर्टरों, महाप्रबन्धक, कावेरी परियोजना कार्यालय, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, उपायुक्त आयकर, तिरुचिरापल्ली, जिला क्लर्क, तिरुचिरापल्ली और इसी प्रकार बड़ी, संख्या में अन्य व्यक्तियों और प्राधिकारियों को समन जारी किए जाएं। अर्जीदार ने यह भी इच्छा व्यक्त की कि प्रत्यर्थी को अपना पासपोर्ट, टेलीफोन के बिल, आयकर और धनकर विवरणियां उसकी उच्चतम शैक्षिक अर्हता का प्रमाणपत्र, उसकी टोयोटा कोरोना कार से संबंधित दस्तावेज, उसके

तीन पुत्रों के अन्य प्रमाणपत्र या विद्यालय प्रमाणपत्र, 1962 से 1984 तक रेल के संबंध में निष्पादित संविदाओं से संबंध वस्तावेजों, जून, 1991 से अप्रैल, 1994 तक संसद सदस्य के कोटे से उसके द्वारा दूसरों को आबंटित किए गए एल पी जो नैस कनेक्शनों और टेलीफोनों से संबंधित और इसी प्रकार के दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए निदेश जारी किए जाएं।

13. उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि अर्जीदार जून, 1991 में लोक सभा के सदस्य के रूप में अपने निर्वाचित होने के पश्चात् संविदा के किसी भी एक ऐसे मामले को उद्घृत करने में असमर्थ रहा है जहां प्रत्यर्थी ने केन्द्रीय सरकार के साथ संविदा की हो, जिससे कि ऐसी संविदा के संबंध में जांच करने की अधिकारिता आयोग को मिल सके। दूसरी ओर, इन संविदाओं का मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष 1990 की निर्वाचन अर्जी सं. 1 में जांच को विषय वस्तु होना निश्चित रूप से यह सिद्ध करता है कि ये संविदाएं प्रत्यर्थी के जून, 1991 में निर्वाचित होने के पश्चात् की नहीं, बल्कि पूर्व में की गई थीं।

14. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए मेरे लिए यह विचार करना आवश्यक नहीं है कि क्या प्रत्यर्थी ने उपरोक्त अभिकथित संविदाओं को "बनामी" द्वारा अपने पुत्र के नाम में किया है। यह कहना पर्याप्त होगा कि अर्जीदार ने अपने अभिकथनों को प्रमाणित करने के लिए कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। प्रत्यर्थी के विद्वान ज्येष्ठ काउंसिल ने सुनवाई के दौरान बोक्षा-प्रमाणपत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत की थी जो यह दर्शाती है कि प्रत्यर्थी के पुत्र जोसेफ लुइस के जन्म की तारीख 11-01-1961 है। जिसका अर्थ यह है कि इस समय उसकी आयु 33 वर्ष से अधिक है। प्रत्यर्थी ने स्पष्ट रूप से यह बताया है कि उनका पुत्र जोसेफ लुइस स्वतंत्र रूप से अपना कारबार करता है। इसके विपरीत किसी भी प्रकार के साक्ष्य के अभाव में उसके द्वारा की गई संविदाओं को प्रत्यर्थी द्वारा की गई संविदाएं नहीं कहा जा सकता, चाहे ऐसी कोई संविदा प्रत्यर्थी के जून, 1991 में लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के पश्चात् ही क्यों न की गई हो। अर्जीदार, बिना किसी उचित आधार के निराधार आरोप लगाकर आयोग से निरुद्देश्य जांच कराने तथा सभी को समन जारी कराने उनके कर्ज से अभिलेख प्रस्तुत कराने की अपेक्षा नहीं कर सकता ताकि अर्जीदार किसी ऐसे वस्तावेज को खोजने में समर्थ हो सके जो उसके उपयोग का हो। अपने मामले को सभी तात्विक विशिष्टियों के साथ यथार्थ रूप से प्रस्तुत करने का भार आर्थिक रूप से अर्जीदार पर ही है तभी वह उसके पश्चात्, इससे संलग्न साक्ष्य समन करने के लिए आयोग के पास जा सकता है न कि वर्तमान मामले की तरह मूर्खतापूर्ण पीछा करने के लिए। अर्जीदार ने, यहां बिना किसी आधार के और उन मुद्दों पर जिनके बारे में वह स्वयं भी सुनिश्चित नहीं है, साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए गवाहों को समन करने के लिए कहे बिना आरोप लगाने के लिए भद्दा मार्ग अपनाया है। आयोग अर्जीदार की ऐसी

लापरवाहीपूर्ण धारणा को अस्वीकार करता है और इसकी निंदा करता है तथा ऐसी निरुद्देश्य जांच का जिसकी अर्जीदार आयोग ने इन कार्यवाहियों में आश्रय लेने की बांछा करता है, पक्षकार बनने से इंकार करता है।

15. सुनवाई के दौरान 18-8-1994 को आयोग द्वारा विशेष रूप से पूछे जाने पर अर्जीदार, विधि में किसी भी ऐसे उपबन्ध को बताने में पूर्णरूप से असफल रहा है जो बैंकों से उधार लेने या नगर भूमि अधिकतम परिसीमा अधिनियम के अतिक्रमण में भूमि और स्थावर संपत्ति क्रय करने या टेलीफोन बिलों का संदाय न करने का पट्टाघृत संपत्ति पर किराए का संदाय न करने या आय-कर अधिनियम और धन-कर अधिनियम के ऐसे अतिक्रमण के लिए, जिसमें सुसंगत अधिनियमों या विधि के अधीन दोषसिद्ध न किया गया हो, संसद का सदस्य चुने जाने या सदस्य होने के लिए निरर्हता का उपबन्ध करता हो। ऐसा प्रतीत होता है कि वह इस प्रभावधीन है कि किसी भी लोप या करण त्रुटि को जो उसके विचार में किसी विधि का अतिक्रमण करती है, संविधान के अनुच्छेद 102(1)(ड) के अधीन निरर्हता के लिए आधार बनाया जा सकता है। अर्जीदार, जो कि विधि व्यवसाय करने वाला अधिवक्ता है, अपने उपरोक्त प्रभाव में गलती पर है। संविधान के अनुच्छेद 102(1)(ड) के अधीन कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हता होगा "यदि वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हता कर दिया जाता है"। संविधान के अनुच्छेद 102(1)(ड) में निविष्ट विधि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 है और उम अधिनियम के भाग 2 के अध्याय 3 में ऐसी निरर्हताओं को विनिर्दिष्ट रूप से अधि-कथित किया गया है। प्रत्यर्थी के अभिकथित उपरोक्त कार्यों में से कोई भी कार्य (अभिकथित अतिक्रमण के लिए, जिन्हें किसी भी विधि के अधीन दोषसिद्ध नहीं मना गया है) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के उक्त अध्याय के किसी भी उपबन्ध के अंतर्गत नहीं आता है।

16. प्रत्यर्थी ने, निष्ठा की अभिस्वीकृति के लिए या केवल इस बात के लिए, कि उसका एक पुत्र सं.रा.प्र. में रहता है या उसके या उसके कुटुंब के विदेशी कंपनियों से कारबारी संबंध हैं या उसके पास विदेश निमित्त कार है, उसकी किसी विदेशी राज्य से अनुषक्ति है, संविधान के अनुच्छेद-102(1)(ड) के अधीन भी कोई निरर्हता प्राप्त नहीं की है। अर्जीदार द्वारा इसमें अधिक न तो अभिकथित किया गया है और नहीं सिद्ध किया गया है।

17. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए मेरी यह राय है और तदनुसार यह अभिनिर्धारित करता है कि प्रत्यर्थी श्री एल. अंदकलराज ने, अर्जीदार द्वारा 03-01-1994 की अर्जी में उल्लिखित आधारों पर, संविधान के अनुच्छेद 102(1) के अधीन निरर्हता उपगत नहीं की है।

18. इस मामले को निपटने से पहले मैं यह विचार व्यक्त किए बिना नहीं रह सकता कि अर्जीदार की वर्तमान अर्जी पूर्ण रूप

से तंग करने वाली अर्जी और संविधान के अनुच्छेद 103 के उपबंधों का दुरुपयोग है। यदि वह आयोग की शक्तियों के अंतर्गत होता तो अर्जिदार द्वारा ऐसी तुच्छ अर्जी प्रस्तुत करने के कारण ऐसे हितकारी उपबंध का दुरुपयोग करने और भारत के राष्ट्रपति तथा निर्वाचन आयोग का मूल्यवान समय नष्ट करने के लिए वह अर्जिदार के विरुद्ध अनुकरणीय खर्च अधिनियमित करना पसंद करता है।

(टी. एन. शेषन)

भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त

नई दिल्ली,

22 अगस्त, 1964

और

अध्यक्ष, भारत निर्वाचन आयोग

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, 28th September, 1994

S.O. 713(E).—The following Order made by the President is published for general information :

WHEREAS, a petition, dated 3-1-1994 has been filed by Shri Thanga Maruthamuthu, an Advocate of Tiruchirappalli alleging that Shri L. Adaikalaraj, a sitting Member of the Lok Sabha has incurred disqualification under clause (1) of article 102 of the Constitution read with section 9A of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951);

AND WHEREAS, the President of India has sought the opinion of the Election Commission under clause (2) of article 103 of the Constitution with reference to the said petition;

AND WHEREAS, the Election Commission is of the opinion (vide Annex) that Shri L. Adaikalaraj has not incurred disqualification under clause (1) of article 102 of the Constitution;

NOW, THEREFORE, I, Shanker Dayal Sharma, President of India, do hereby dismiss the aforesaid petition of Shri Thanga Maruthamuthu.

September 19, 1994.

PRESIDENT OF INDIA

[No. 7(43)/94-Leg. II]

T. K. VISWANATHAN, Jt. Secy. and Legislative Counsel

ANNEX

ELECTION COMMISSION OF INDIA

BEFORE THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

Reference Case No. 1 of the 1994

[Reference from the President of India under Article 103(2) of the Constitution of India]

OPINION

This is a reference from the President of India under Article 103(2) of the Constitution of India seeking the opinion of the Election Commission of India on the question whether Shri L. Adaikalaraj, a sitting member of the House of the People elected from 27-Tiruchirappalli Parliamentary Constituency in the State of Tamil Nadu in June, 1991, has become subject to disqualification under Article 102(1) of the Constitution.

2. The above question has been raised before the President of India in terms of Article 103(1) of the Constitution by one Shri Thanga Maruthamuthu, Advocate of Tiruchirappalli by his petition dated 03-01-1994.

3. The petitioner has alleged that the respondent, Shri L. Adaikalaraj, has incurred disqualification under 102(1) of the Constitution read with Section 9A of the Representation of the People Act, 1951 (hereinafter referred to as '1951-Act') or having entered into several contracts for the construction and maintenance of buildings and execution of civil works undertaken by the Southern Railways. He has alleged that though these contracts have been entered into in the name of the respondent's son, these are in fact the contracts entered into by the respondent in the course of his trade and business. It seems apt to state the petitioner's allegations to the above effect in his own words as put by him in his above-mentioned petition to the President :—

“3. The Respondent's father Late A.S.G. Lourdu-samy was executing contracts of construction and maintenance works of buildings with Southern Railway Tiruchirappalli Division and also had a Petrol Bunk on the land leased by Southern Railway Tiruchirappalli.

(4) The Respondent has got the contracts of construction works and maintenance works of buildings with Southern Railways Tiruchirappalli Division which were standing in the name of his father Late Sri A.S.G. Lourdu-samy Pillai.

(5) (i) The Respondent has entered into contracts in the name of his son Joseph Louis with Southern Railway, Tiruchirappalli Division for execution of civil works for construction of :

(a) a over-bridge at Goodshed Road on Tiruchirappalli-Pudukkottai Road at a distance of @ 1/2 Km.-at a cost of @ Rs. 3.5 crores.

- (b) Buildings for Railway Stations,
 - (c) Hospital, and
 - (e) Other buildings.
- (ii) The respondent has entered into contracts with Southern Railway, Tiruchirappalli District in the name of his son Joseph Louis for the execution of Maintenance works of buildings belong to Southern Railway in Tiruchirappalli Division.
- (iii) Because of the respondent being a sitting Member of Parliament, has influenced a Railway employee namely Mr. M. Gopalan, S/o R. Nataraja Iyer, 22 Mandhi Koil Street, Trichy-2 and received huge amount from Southern Railway for works not executed and received enhanced rates of payment for the works done all in the name of his son Joseph Louis.
- (iv) The respondent is occupying the building near RPF Office, Tiruchirappalli-1 belong to Southern Railway for the purpose of execution of contract works with Southern Railway. The respondent's telephone No. 41155 was installed at the above said Railway building for execution of contract works with Southern Railway.
- (v) The respondent through his family business L.A. Group has provided Housing accommodation to Senior Electronic Data Processing Manager—Computer Centre, Southern Railway at 4-AR Apartments, Tiruverumbur, Tiruchirappalli-13.
- (vi) The respondent has interest in his family business—Execution of contract works of construction of the above said bridge and buildings and maintenance of buildings with Southern Railway—Tiruchirappalli Division.
- (vii) The respondent is the real contracting party. His son Joseph Louis is a mere name lender. The contracts between the respondent's family business L.A. Group in the name of his son Joseph Louis and Southern Railway, have been entered into on behalf of and for the benefit of the joint family in which the respondent is the head.
- (viii) The respondent has availed and availing emergency quota facilities for accommodation in trains for the benefit of his family business by using his official Member of Parliament letter pad having the logo of Government of India.
- (6) The law requires that a candidate should not have any interest in any contract with Government and even a partner has an interest is sufficient to attract the provisions of Sec. 9-A of the Representation of the People Act, 1951.
- (7) From the facts stated above in paragraphs 3, 4, 5 and as per the law stated in paragraph 6 the respondent has violated Sec. 9-A of the Representation of the People Act, 1951, when he had entered into contracts in the name of his son Joseph Louis with the Government of India—Southern Railway—Tiruchirappalli Division, which are subsisting new and hence the respondent stands disqualified for being chosen as and for being a Member of either house of Parliament under Art. 102(1)(e) of the Constitution of India.
- (8) (i) The respondent is doing Hotel business as a family business and has a three star hotel namely Jennys Residency (Formerly called as Rajali Hotel, worth about Rs. 6 crores at 3/14, Macdonalds Road, Tiruchirappalli-1. The respondent's son, A. Joseph Francis, (aged 23 years in 1991) is the Managing Director of this Hotel, his third son, A. Joseph Vincent (aged 21 years in 1991), his wife Smt. Rani Adaikalaraj and his daughter-in-law Smt. Shiela Louis (aged 20 years in 1991) are the Directors of the Hotel, Smt. Shiela Louis is the wife of his first son Joseph Louis, the name lender for his contracts with Southern Railway.
- (ii) Through the above said hotel, the respondent is providing catering and accommodation facilities to Union Government departments and Government of India undertakings viz. Oil and Natural Gas Commission, Cauvery & Narimanam Projects.
- (9) From the facts stated above in paragraph-8, the respondent has violated Sec. 9-A of the Representation of the People Act, 1951 and hence stands disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament under Act 102(1)(e) of the Constitution of India.
- (10) (b) The respondent had sold a floor of his family business building Jenny Plaza to Indian Bank at a very high rate without following the norms prescribed for valuation of the building after entering into a contract for sale of the above said building, in which the Zonal Office, Indian Bank, Tiruchirappalli is functioning now.
- (11) From the facts stated above in paragraph 10, the respondent and his sons were doing joint family business of which the respondent is the Chairman and the head of the family. They were doing the business for the benefit of the joint family. The respondent has interest in all the contracts carried out by his family business with the nationalised bank + Indian Bank in availing loan or their companies and in the sale of one floor of their building and hence the provisions of Sec. 9-A, of Representation of People Act, 1951 attracts, so that

respondent stands disqualified for being chosen as and for being a Member of either house of Parliament under Art. 102 (1)(e) of the Constitution of India.

- (16) (i) The respondent, "the arrack king" and M. P. had resorted to all kinds of tamanny hall tactics in putting pressure on the LATE Rajiv Gandhi in clearing the Pepsi Project. The respondent was awarded the highly remunerative Franchise for the south by each of the three partners in the project—Pepsico, Voltas and the Public Sector Punjab Agro-Industries Corporation. By accepting the above said contract the Respondent has violated Sec. 9-A of the R. P. Act, 1951.

- (23) The respondent has taken a contract with Government of India's Indian Oil Corporation Ltd.—Lubes Godown operated in the name of M/s. A.S.G. Lourdasamy Pillai & Sons, at 114/1-B, Bye Pass Road, Tiruchi-10 attracting Sec. 9-A of the Representation of the People Act, 1951 and thereby stands disqualified for being chosen and for being a member of either house of Parliament under Art. 102(1)(e) of the Constitution of India.

- (24) The Respondent's LA Group has entered into a contract with National Insurance Co. Ltd., and provided office accommodation at their AR Building, Tiruverumbur, Trichy-13. By this act the respondent has violated Sec. 9-A of the Representation of the People Act, 1951 and hence stands disqualified for being chosen as and for being a member of either house of Parliament under Art. 102(1)(e) of the Constitution of India."

4. The petitioner has also alleged that the respondent has incurred disqualification under Article 102(1)(e) of the Constitution by amassing huge wealth disproportionate to his known sources of income, by purchasing vast properties in violation of the Urban Land Ceiling Act, by raising loans of large amounts from the banks for his family business misusing his official position, by not paying telephone bills, by not paying rent of a cinema theatre taken on lease from the Tiruchirappalli District Welfare Fund Committee and by making a false declaration that he completed diploma in Civil Engineering.

5. The petitioner has also alleged that the respondent is disqualified for acknowledging allegiance or adherence to a foreign State under Article 102(1)(d) of the Constitution as he is involved in international monetary laundering operations through one of his sons, who stays in U.S.A., and his family possesses a Japanese make Toyota Corona Car.

6. The respondent has, in his written statement dated 07-03-1994, denied all the allegations of the

petitioner. He has stated that all the contracts mentioned by the petitioner have been taken by his son who is major and is doing his independent business and that he has nothing to do with those contracts since 1984 when he was elected to the House of the People for the first time. He has also pointed out that this very petitioner had raised the questions of those very contracts in Election Petition No. 1 of 1990 before the Madras High Court which he filed challenging the election of the respondent to the House of the People held in 1989 and that the Madras High Court by its order dated 02-07-1993, dismissed that election petition rejecting the petitioner's allegations. He has stated that the decision of the Madras High Court amounts to res judicata and the petitioner cannot be permitted to get the same matter adjudicated before the President and the Election Commission under Article 103 of the Constitution.

7. The respondent has also specifically denied in his aforesaid written statement all allegations relating to amassing of wealth disproportionate to the known sources of income, raising of loans from Banks, purchase of immovable property, non-payment of telephone bills, non-payment of rent on the that he is under acknowledgement of any allegiance lease property, etc. The respondent has also denied or adherence to a foreign State.

8. Both the petitioner and the respondent were heard by the Commission on 18-08-1994. Whereas the petitioner appeared in person, the respondent was represented through his learned senior counsel Shri C. S. Vaidyanathan.

9. Before I deal with the allegations of the petitioner and the oral submissions made by him in support of the same and the oral submissions of the learned counsel for the respondent in the rebuttal of those allegations, it would be appropriate to state the constitutional and legal position as to the jurisdiction and scope of the inquiry which the President and the Election Commission can make in terms of Article 103 of the Constitution. It is now well settled by a catena of decisions of the Supreme Court in Election Commission Vs. Saka Venkata Rao (AIR 1953 SC 210), Brundaban Navak Vs. Election Commission of India (AIR 1956 SC 1982), Election Commission Vs. M. G. Ranga (AIR (1978 SC 1609), etc., that under Article 103 only those questions of disqualification of a sitting member of Parliament can be raised before the President and inquired into by the Election Commission to which the member has become subject after his election as such member. In other words, the Commission can inquire under Article 103 only into the questions of post-election disqualification of member. Any question relating to a disqualification to which such member was subject prior to or at the time of his election, i.e. pre-election disqualification can be raised only by means of an election petition presented to the High Court concerned in accordance with the provisions of Article 329(b) of the Constitution read with Part VI of the Representation of the People Act, 1951.

10. Therefore, the Election Commission in the presented proceedings under Article 103 can inquire

into only those contracts which the respondent entered into after his election to the House of the People in June, 1991. Further, it is not every kind of contract which attracts the disqualification clause of section 9A of the 1951 Act. Under that section, only two types of contracts with the appropriate Government attract the provisions relating to disqualification, namely, (i) contracts for the supply of goods to the appropriate Government, and (ii) contracts for execution of any works undertaken by that Government. The 'appropriate Government', by virtue of definition in Section 7(a) of the 1951-Act will, in the present case, mean the Central Government.

11. The petitioner has nowhere stated in his petition as to which of the contract—even if it be assumed in his favour that the contracts made in the name of the respondent's son were made by the respondent—were entered into and executed after the respondent's election to the House of the People in June, 1991. In fact the date of not even a single contract has been mentioned anywhere in the entire petition.

12. The petitioner was specifically asked at the hearing to state the dates of alleged contracts. He failed to cite even one date or even some approximate date of any contract. He stated that he would like the authorities concerned like the Divisional Manager, Southern Railways to produce all the contracts entered into by that railways with the respondent's father or the respondent or the respondent's son from 1962 to 1992. Similarly, he wanted the Commission to issue summons to a large number of other persons and authorities, like, the Chairman of Indian Bank, General Managers of Telecommunications, Tiruchirappalli, Madras, New Delhi, Editors, Advertisement Managers and Reporters of several newspapers, like, The Hindu, Surya India, Indian Express, Dinnamalar, Thanthi, General Manager, Kaveri Project Office, Oil and Natural Gas Commission, Deputy Commissioner, Income Tax, Tiruchirappalli, District Collector, Tiruchirappalli and so on. The petitioner also desired directions to be issued to the respondent to produce his passport, telephone bills, income tax and wealth tax returns, certificate of his highest educational qualification, documents relating to his Toyota Corona Car, birth certificates or school certificates of his three sons, the documents relating to contracts executed for railways from 1962 to 1984, documents relating to LP Gas connections and telephones allotted by him to others from the MP's quota from June 1991 to April 1994 and so on.

13. It is evident from the above that the petitioner has not been able to cite even a single case of a contract entered into by the respondent with the Central Government after his election as member of the House of the People in June, 1991 which would give jurisdiction to the Commission to make an enquiry into such contract. On the other hand, the very fact that these contracts were subject matter of inquiry in Election Petition No. 1 of 1990 before the Madras High Court conclusively prove that these contracts were entered into before, and not after, the election of the respondent in June, 1991.

14. In view of the above, it is not necessary for me to go into the question whether the alleged contracts have been made 'benami' by the respondent in the name of his son. Suffice to say that the petitioner has not produced even an iota of evidence to substantiate his allegations to that effect. The learned senior counsel for the respondent produced at the hearing photocopy of the baptism certificate which shows the date of birth of the respondent's son Joseph Louis as 11-01-1961 which means that he is more than 33 years old at present. The respondent has categorically stated that his son Joseph Louis is running his own independent business. In the absence of any evidence to the contrary, the contracts entered into by him cannot be said to be the contracts entered into by the respondent, even if any such contract was entered into after the election of the respondent to the House of the People in June, 1991. The petitioner cannot make a wild allegation without laying a proper foundation and require the Commission to make a roving and fishing enquiry and issue summons to all and sundry to produce records in their possession for the purpose of enabling the petitioner to find out whether any such document is capable of being made use of by him. The onus initially lies on the petitioner to state his case precisely with all material particulars and then only can he approach the Commission for summoning the evidence relevant thereto and not for a wild goose chase as in the present case. The petitioner herein has adopted a novel way of making an allegation without laying foundation and asking for witnesses to be summoned to tender and adduce evidence on aspects about which he himself is not sure. The Commission rejects and severely condemns such cavalier approach of the petitioner and refuses to be party to a roving and fishing enquiry which the petitioner desires the Commission to embark upon in these proceedings.

15. The petitioner, when specifically asked by the Commission at the hearing on 18-08-1994, also abysmally failed to point out even a single provision in the law which provides for disqualification for being chosen as, or for being, a member of Parliament for raising loans from the banks or purchasing land and immovable property in violation of the Urban Land Ceiling Act or non-payment of telephone bills or non-payment of rent on leased property or for violations of Income Tax and Wealth Tax Acts, which have not resulted in any conviction under the relevant Acts or the laws. He seemed to be labouring under the impression that any act of omission or commission which he considered to be violative of any law can be urged as a ground for disqualification under Article 102(1)(c) of the Constitution. The petitioner who is a practising Advocate is sadly mistaken in his above impression. Under Article 102(1)(c) of the Constitution, a person shall be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament "if he is so disqualified by or under any law made by Parliament". The law referred to in Article 102(1)(c) of the Constitution is the Representation of the People Act, 1951 and Chapter III of Part II of that Act specifically lays down such disqualifications. None of the aforesaid alleged acts of the respondent (which have not led to any conviction under

any law for alleged violations thereof) fall within any of the provisions of the said Chapter of the Representation of the People Act, 1951.

16. The respondent can also not be said to have incurred any disqualification under Article 102(1)(d) of the Constitution for acknowledgment of allegiance or adherence to a foreign State merely because one of his sons lives in U.S.A. or he or his family has business dealings with foreign companies or owns a foreign make car. Nothing more than this has been alleged or proved by the petitioner.

17. Having regard to the above, I am of the opinion and accordingly hold that the respondent Shri L. Adaikalaraj has not incurred disqualification under Article 102(1) of the Constitution on the grounds mentioned by the petitioner in his petition dated 03-01-1994.

18. Before parting with the present case, I cannot help expressing the view that the present petition of the petitioner is a purely vexatious petition and an abuse of the provisions of Article 103 of the Constitution. If it were in its powers, the Election Commission would have liked to award exemplary costs against the petitioner for having abused a salutary provision and having wasted the invaluable time of the President of India and the Election Commission by making such a frivolous petition.

New Delhi.

22nd August, 1994.

T. N. SESHAN,

Chief Election Commissioner of India
and Chairman, Election Commission of India.